गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 300
दि. 03.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मिसाइल हमलों में फंसे 310 यात्री अबू धाबी से दिल्ली सुरक्षित पहुंचे, परिवार को देख छलके खुशी के आंसू

नई दिल्ली, (जीएनएस)।

अबु धाबी से सोमवार को एतिहाद एयरवेज की एक उड़ान 310 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची। ये यात्री ईरान के खाड़ी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमलों के कारण वहीं फंसे थे। ईरान ने ये हमले शनिवार से हुए अमेरिका-इजरायल मिसाइल हमलों की जवाबी कार्रवाई में किए थे।

यह उड़ान सोमवार रात 8:30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर उतरी। यात्रियों के बाहर आते ही उनके परिजन उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। हवाई अड्डे पर बेहद भावनात्मक माहौल था, जहां कई परिवारों का पुनर्मिलन हुआ।

55 वर्षीय विनोद शर्मा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया, "मेरा बेटा शिव शनिवार को मैनचेस्टर से अबू धाबी के रास्ते लौट रहा था पर वहीं फंस गया। हम बेहद डरे थे, क्योंकि उसने बताया कि उसे होटल के ऊपर मिसाइलें इंटरसेप्ट होते दिखीं और सुनीं। हमने उड़ान लगातार ट्रैक की और भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही राहत महसूस की।"

टर्मिनल पर इंतजार कर रहीं 50 वर्षीय दानिश्ता परवीन ने अपनी बेटी (एतिहाद क्रू मेंबर) के बारे में बताया, "वह वैसे तो 28 फरवरी को आने वाली थी, पर आ नहीं सकी... उसने हमें बताया कि मिसाइलों के कारण हवाई अड्डे की दीवारें हिलती महसूस हुईं। कल उसका जन्मदिन है, तो मैं खुश हूँ कि वह लौट आई है और अब हमारे साथ इसे मना पाएगी।"

अपने बेटे और बहू के साथ लौटीं 52 वर्षीय शशि परमार ने घर पहुंचकर खुशी जताई। उन्होंने कहा, "हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या होगा, और हम बहुत लंबे समय तक वहीं फंसे रहने को लेकर चिंतित थे। बच्चों के साथ दिल्ली में आकर मुझे राहत मिली है; पिछले दो दिनों में पहली बार अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ।"

42 वर्षीय राहुल कुमार को 28 फरवरी को उड़ान भरनी थी, हवाई अड्डे पर उन्हें बोर्डिंग पास भी मिल गया था। पर ईरान के मिसाइल हमलों के कारण अधिकारियों को विमानों को खड़ा करना पड़ा।

कुमार ने बताया, "मुझे 28 तारीख को ही वापस लौटना था, मेरा बोर्डिंग पास भी तैयार था, पर फ्लाइट निलंबित कर दी गई। इसके बाद हमने आसमान में कई बार मिसाइलों को इंटरसेप्ट होते देखा। हमें अपने होटल पर उन्हीं से गिरता मलबा भी महसूस हुआ, जो मेरे परिवार और मेरे लिए बहुत डरावना था।"

कनाडा से लौट रहीं 50 वर्षीय हरपिंदर सिद्धू अबू धाबी में स्टॉपओवर पर फंस गई थीं।

उनका कहना था, "हमने मिसाइलों की आवाज भी सुनी, पर अधिकारियों ने घबराहट को फैलने नहीं दिया।" अन्य यात्रियों ने भी

मुश्किल हालात में सहजता बनाए रखने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की।

32 वर्षीय प्रज्वल वर्मा भी टोरंटो से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, पर उनकी उड़ान रद्द हो गई थी। उन्होंने साझा किया, "हमने कुछ बार मिसाइलों की आवाज सुनी और डर गए थे। पर अब मैं वापस आकर राहत महसूस कर रहा हूँ; मैं अकेला यात्रा कर रहा था, इसलिए परिवार से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा है।"

60 वर्षीय अंजना गुप्ता अपने बेटे और बहू की वापसी से बेहद खुश थीं। उन्होंने कहा, "पिछले दो दिनों से, वे हमें आसमान में हुए धमाकों और उनके होटल की खिड़कियों के हिलने के वीडियो भेजते थे, जिससे हम बहुत डर जाते थे। इसलिए मैं खुश हूँ कि वे सकुशल वापस आ गए हैं।"

रेवेन्यू केसों को निपटाने में लखनऊ नंबर वन, जिला कोर्ट में जौनपुर ने फिर मारी बाजी

लखनऊ सबसे अधिक राजस्व मामले निस्तारित करने में अव्वल रहा है। वहीं, जिला कोर्ट में जौनपुर ने एक बार फिर बाजी मारी है। जौनपुर 15 माह से टॉप 5 में बना है।

लखनऊ: , (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू केसों को निपटाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष जोर दिया है। उनके निर्देशों का असर है कि इन केसों को तेजी से निस्तारित किया जा रहा है। मामलों की मुख्यमंत्री के स्तर पर मॉनीटरिंग हो हो रही है। राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में मुख्यमंत्री की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ दिख रहा है। हर माह जिलावार मामलों की समीक्षा होती है। राजस्व कोर्ट कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) की फरवरी माह की रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में मामलों को निस्तारित किया गया है। वहीं, जिला स्तरीय कोर्ट में राजस्व के मामले निपटाने में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी मारी है। जिला स्तरीय कोर्टों में राजस्व वादों के निस्तारण में पिछले 15 माह से जौनपुर टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है।

राजधानी में सबसे अधिक मामले निस्तारित

योगी आदित्यनाथ सरकार की विशेष पहल के तहत तेजी से मामलों के निपटारे की रणनीति को अपनाया गया। इससे राजस्व विवादों के मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिला है। नतीजा पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश भर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी है। सीएम के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। उनकी इस पहल का उद्देश्य न केवल जनता को त्वरित न्याय दिलाना है, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देना है।

सीएम योगी के निर्देश के तहत प्रदेश के डीएम और अन्य संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता से मामलों का निस्तारण कर रहे हैं।

राजस्व परिषद की आरसीसीएमएस की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में पूरे प्रदेश में कुल 3,34,538 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया कि सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में 15,981 मामले निस्तारित किए गए। डीएम ने कहा कि यह पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद प्रयागराज में कुल 14,132 मामलों को निस्तारित कर पूरे प्रदेश में दूसरा, आजमगढ़ 9333 मामलों को निस्तारित कर तीसरे स्थान पर है।

लखनऊ में सबसे अधिक 15,981 राजस्व मामलों को निपटया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत राजस्व मामलों को प्रमुखता के साथ निपटाया जा रहा है।

विशाख जी अय्यर, लखनऊ डीएम

राजस्व मामले सर्वोच्च प्राथमिकता

आजमगढ़ डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं। रेवेन्यू कोर्ट में लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निपटाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आजमगढ़ ने फरवरी में राजस्व मामलों के निस्तारण में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह जौनपुर ने 8912 मामले निस्तारित कर चौथा और बाराबंकी ने 8378 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

जिला कोर्ट में जौनपुर ने मारी बाजी

जौनपुर डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार राजस्व मामलों को निस्तारित किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू की फरवरी माह की राजस्व कोर्ट कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार जौनपुर की पांच राजस्व कोर्टों ने बोर्ड के निर्धारित मानक के निस्तारण से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जौनपुर की पांच राजस्व कोर्टों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 से दोगुने से अधिक 542 मामलों का निस्तारण किया है। इसका अनुपात 216.80 प्रतिशत है।

हर कपल की यात्रा एक जैसी नहीं होती

डीएम ने कहा कि इसी के साथ जिला कोर्ट में राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, मानक 300 के सापेक्ष 381 मामलों का निस्तारण कर दूसरे स्थान पर बस्ती और मानक 300 के सापेक्ष 353 मामले निस्तारित कर तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है। इसी तरह फरवरी में जौनपुर के जिलाधिकारी कोर्ट ने निर्धारित 30 मामलों के मानक के मुकाबले 86 मामलों का निस्तारण कर 286.67 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की।

रक्षा राज्य मंत्री ने ओमान की अपनी पहली विदेशी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद आईएनएसवी कौंडिन्य का स्वागत किया

श्री संजय सेठ युवाओं को सभ्यतागत आत्मविश्वास पर आधारित साहसिक कार्य और नवाचार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं

(जीएनएस)।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 2 मार्च, 2026 को मुंबई के नौसेना गोदी में भारतीय नौसेना के पारंपरिक रूप से निर्मित पोत कौंडिन्य का स्वागत किया। यह पोत मस्कट, ओमान की अपनी ऐतिहासिक पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद स्वदेश लौटा है। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने परियोजना के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आईएनएसवी कौंडिन्य भारत की प्राचीन समुद्री ज्ञान प्रणालियों के पुनरुद्धार का प्रतीक है। उन्होंने कहा यह परियोजना देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। श्री सेठ ने इस यात्रा में प्रदर्शित साहस, दृढ़ता और

पुनर्खोज की भावना को रेखांकित करते हुए युवा भारतीयों को सभ्यतागत आत्मविश्वास पर आधारित साहसिक और नवाचार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर, पश्चिमी नौसेना कमान के ध्वज अधिकारी कमान-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने अरब सागर में पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज को सफलतापूर्वक चलाने में चालक दल के असाधारण समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना की। उन्होंने अवधारणा और अनुसंधान से लेकर डिजाइन, पारंपरिक निर्माण, चालक दल के प्रशिक्षण और यात्रा के क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया में शामिल अथक परिश्रम पर बल दिया।

आधुनिक संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के बिना, वगार्कार पाल वाली, लकड़ी से बनी नाव को संचालित करने के लिए असाधारण योजना, नाविक कौशल, टीम वर्क और सहनशक्ति की आवश्यकता थी। इससे इस अभियान का सफल समापन भारतीय नौसेना के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि बन गया है।

जैसे ही आईएनएसवी कौंडिन्य ने औपचारिक प्रवेश किया, रंगारंग पाल जुलूस और पारंपरिक जल चाप सलामी के साथ उसका स्वागत किया गया, इससे बंदरगाह में एक शानदार और भावपूर्ण वातावरण बन गया। यह आयोजन भारत की समुद्री विरासत पर गर्व और चालक दल की उपलब्धि के प्रति प्रशंसा का प्रतीक था। मुंबई में ओमान के महावाणिज्यदूत श्री महबूब ईसा अलरैसी, वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक, होडी इनोवेशन के प्रतिनिधि, नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य, समुद्री समुदाय के सदस्य, इतिहासकार और नौकायन के शौकीन इस अवसर पर उपस्थित थे। आईएनएसवी कौंडिन्य भारतीय नौसेना का 20 मीटर लंबा, पारंपरिक रूप से निर्मित एक जहाज है, यह अजंता गुफाओं में मिली 5वीं शताब्दी ईस्वी की एक कलाकृति से प्रेरित है।

प्राचीन भारतीय जहाज निर्माण तकनीकों (लकड़ी के तख्तों को नारियल की रस्सी से बांधकर प्राकृतिक रेजिन से सील करने का काम) का उपयोग करके निर्मित यह जहाज भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के पुनरुद्धार का प्रतीक है।

संक्षिप्त समाचार

सिविल सेवाओं से भर्ती हुए और एलबीएसएनएए में 128वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की

राज्य सिविल सेवाओं से भर्ती हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में आयोजित 128वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने आज (2 मार्च, 2026) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने बहरीन के शाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बहरीन के शाह, महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन पर हाल ही में हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस कठिन घड़ी में बहरीन की जनता के प्रति भारत की दृढ़ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने बहरीन में रहने वाले भारतीय समुदाय को प्रदान किए गए निरंतर सहयोग और देखभाल के लिए महामहिम शाह का आभार भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए लिखाः "बहरीन के शाह, महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक टेलीफोन वार्ता हुई।

प्रधानमंत्री 3 मार्च को 'सतत और सशक्त आर्थिक विकास' विषय पर बजट-पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री 3 मार्च, 2026 को सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "सतत और सशक्त आर्थिक विकास" विषय पर आयोजित बजट-पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के अंतर्गत, चार अलग-अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों - (i) विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्र, (ii) लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त और बाजार पहुंच, (iii) शहरी आर्थिक क्षेत्र और (iv) अवसंरचना, रसद और माल ढुलाई को शामिल किया गया है। बजट-पश्चात वेबिनार में औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नेतृत्व को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जा रहे दूरदर्शी सुधारों पर प्रकाश डाला जाएगा।

आज से लेकर चार मार्च तक बंद रहेगा चिड़ियाघर, तीन मार्च तक इमामबाड़े पर लगे रहेंगे ताले; जानिए वजह

लखनऊ , (जीएनएस)। होली के मौके पर लखनऊ का चिड़ियाघर आज से लेकर चार मार्च तक पूरी तरह से बंद रहेगा। उधर खामनेई की मौत की वजह से इमामबाड़ा तीन मार्च तक बंद रहेगा।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) होली पर्व पर तीन दिन बंद रहेगा। इस अवधि में दर्शक चिड़ियाघर नहीं घूम सकेंगे। चिड़ियाघर के निदेशक संजय कुमार बिस्वाल के अनुसार, सोमवार को चिड़ियाघर में सार्वजनिक अवकाश रहता है। जबकि, मंगलवार और बुधवार को होली पर्व पर छुट्टी की गई है। 5 मार्च को प्राणी उद्यान पूर्व की तरह खुलेगा।

तीन मार्च तक बंद रहेगी भूलभुलैया

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में शिया समुदाय की ओर से तीन दिन तक शोक व प्रदर्शन का एलान किया

गया है। एहतियात के तौर पर बड़ा इमामबाड़ा (भूलभुलैया) और छोटा इमामबाड़ा तीन मार्च तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। एडीएम (पूर्वी) महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि खामनेई की हत्या के विरोध में शिया समुदाय के लोगों ने तीन दिन तक शोक और प्रदर्शन का एलान किया है। उनकी धार्मिक भावनाओं, शांति व पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि तीन मार्च के बाद दोनों इमामबाड़े पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की हत्या पर शिया समुदाय में आक्रोश को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार सुबह से प्रदर्शन के कारण सभी थानेदारों व एसीपी को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है।

सफल रहा प्रदेश सरकार का मीन महोत्सव, लखनऊ में पहली बार हुआ आटो एक्पो आयोजन

उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो 2026 का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया

मत्स्य क्षेत्र में होगा 1400 करोड़ रुपये का निवेश

30 कंपनियों ने दिया निवेश का प्रस्ताव

प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कोशिश शुरू

लखनऊ। , (जीएनएस)। प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र में 1400 करोड़ रुपये का निवेश निवेश होने जा रहा है। हाल ही में मीन महोत्सव में 30 कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे पहले मत्स्य शिखर सम्मेलन में भी विभिन्न कंपनियों के निवेश प्रस्ताव आए थे। मत्स्य विभाग अब इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में जुट गया है।

लखनऊ में पहली बार आयोजित

दो दिवसीय उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो 2026 ने मत्स्य पालन को आधुनिक तकनीक, निवेश और उद्यमिता से जोड़ने का मंच दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय और प्रदेश सरकार की योजनाओं, नई तकनीकों और बाजार से सीधे जुड़ाव पर फोकस रहा। मत्स्य विभाग ने 27 और 28 फरवरी को लखनऊ में मीन महोत्सव का आयोजन किया था। जिसमें देश भर के उद्यमी, निवेशक और वैज्ञानिक शामिल हुए थे।

विभाग के अनुसार आयोजन में 1200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से औरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी में 300 करोड़ रुपये निवेश करेगी। प्रोबस स्मार्ट थिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड तथा नेक्सजेन कंपनियां 200-200 करोड़ रुपये का निवेश करना चाहती हैं।

दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने बाराबंकी में 100 करोड़ रुपये निवेश करने की इच्छा जताई है।

आंध्र प्रदेश की नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक श्रीनिवास के अनुसार उनकी कंपनी फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी। जिसमें 150 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह प्लांट 2028 तक तैयार हो जाएगा। इससे पहले दिसंबर में हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में भी विभाग को 207 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। महानिदेशक मत्स्य धनलक्ष्मी के. ने बताया कि परियोजनाओं को जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए विभाग निवेशकों को आवश्यक सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराएगा।

श्री बी.पी. सिंह ने नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया

श्री बी. पी. सिंह ने 1 मार्च, 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक (डीजीओएनए) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय नौसेना आयुध सेवा (आईएनएएस) के 1994 बैच के अधिकारी बी. पी. सिंह ने श्री दिवाकर जयंत का स्थान लिया, जो राष्ट्र की विशिष्ट सेवा के पश्चात 28 फरवरी, 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

पटना स्थित बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (वर्तमान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री बी. पी. सिंह नौसेना आयुध संगठन में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध और बहुआयामी अनुभव रखते हैं। वे डीजीओएनए के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मुंबई स्थित नौसेना आयुध डिपो (एनएडी) में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण परिचालन, रसद एवं अवसंरचना संबंधी गतिविधियों का कुशल नेतृत्व किया। श्री बी. पी. सिंह ने एनएडी विशाखापत्तनम, एनएडी मुंबई और एनएडी ट्रॉम्बे सहित कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

अवकाश की सूचना

हमारे प्रिय पाठकों को सूचित किया जाता है कि होली पर्व के अवसर पर कार्यालय में 04 मार्च 2026 को अवकाश होने के कारण 05 मार्च का समाचार पत्र नहीं मिल सकेगा। अगला समाचार पत्र 06 मार्च, 2026 शुक्रवार के दिन प्राप्त हो सकेगा।

- सम्पादक

सम्पादकीय

ईरान का डांवाडोल भविष्य

नोबेल पीस प्राइज के दावेदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके परंपरागत एवं चिरपरिचित शत्रु इजरायल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई सहित प्राथम एवं द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का सफाया कर दिया और लगभग 40 सैन्य कमांडरों को मार डाला। राजनीतिक नेतृत्व विहीन और सैन्य मार्गदर्शक नेतृत्व के अभाव में अब ईरान अपने पड़ोसी मध्यपूर्व के देशों पर हमले कर रहा है। वह इजरायल के तेल अवीव पर भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान में घुसे सीआईए और मोसाद ने पहले ही जमीनी तैयारी इस तरह कर ली थी कि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य कमांडरों के हर मूवमेंट की जानकारी उन्हें हासिल हो जाती थी और उसी के अनुसार वे अपनी रणनीति के मुताबिक ईरानी राजनीतिक एवं सेना अधिकारियों को निशाना बनाते रहे।

यह सच है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्राधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिन तीन लक्ष्यों यानि परमाणु हथियार एवं सामग्री और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को नष्ट करना तथा नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए तेहरान पर हमले किए उन्हें प्राप्त करने में अब कोई संदेह नहीं लग रहा है। ईरान पर इस बार अमेरिका और इजरायल ने पूरी तैयारी से हमला किया है। शीर्ष राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व का सफाया हो जाने के कारण सेना के स्थानीय अधिकारी खुद ही पैसले ले रहे हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि अब उनके पास जब वुछ खोने को है ही नहीं तो क्यों न उन पड़ोसी मुल्कों को सबक सिखाए जो किसी न किसी रूप में अमेरिका के हितों के लिए साधन बने हुए हैं।

यह सच है कि ईरान में तमाम राजनेता भी हैं जो असंतुष्ट हैं और अपने बयानों के कारण वे जेल में बंद हैं। यदि अमेरिका उन राजनीतिक वैदियों को छुड़ा देता है तब तो यह माना जा सकता है कि अमेरिका और इजरायल जल्दी से जल्दी कोई वैकल्पिक सरकार बनाना चाहते हैं। ईरान के पूर्व शासक रजा पहलवी के अलावा भी अमेरिका और इजरायल के पास विकल्प होंगे, यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आम जनता को सलाह दी कि वे सामने आकर अपनी सरकार बना लें।

इतना तो निर्विवाद है कि अमेरिका ने हमले करके किसी भी देश पुनर्निमाण की जरूरत नहीं समझा है। इसलिए आज जिस तरह से ईरान में विध्वंस का बारूदी खेल चल रहा है, उसने इस देश को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया है। सीआईए और मोसाद ने न सिर्प ईरानी इंटेलीजेंस ब्यूरो कार्य प्राव्रिया को प्राभावित कर दिया है, वहीं बहुत सारे ईरानी इंटेलीजेंस के प्रातिनिधियों को खरीद लिया है। ईरानी इंटेलीजेंस ब्यूरो के एजेंटों ने ही शीर्ष नेताओं और सैन्य कमांडरों की सूचना अमेरिका और इजरायल के खुफिया प्रातिष्ठानों को दी है। बहरहाल ईरान में यदि कोई राजनीतिक सत्ता होती तो उसमें इतनी बौखलाहट न होती कि वह अपने सारे पड़ोसियों को अपने हमलों की वजह से अपना दुश्मन बनाता।

लब्बोलुआब यह है कि अमेरिका और इजरायल अब ईरान में उसके परमाणु संयंत्रों एवं सामग्री को समेटने की तैयारी में हैं साथ ही ईरान के बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम को तबाह करने की तरफ भी बढ़ चुके हैं। अब यदि अमेरिका ने एक बार फिर इराक, लीबिया और सीरिया की तरह ही ईरान को भी बर्बाद करके छोड़ना है और उसके पुनर्निर्माण की कोई नीति या कार्य योजना नहीं है तो ईरान के बौखलाए सैनिक इजरायल और अपने पड़ोसियों पर छिटपुट हमले करते रहेंगे और मध्यपूर्व में तनाव की आग धधकती रहेगी साथ ही पामि एशिया में भी अशांति रहेगी, जिससे सारे मुस्लिम देश प्राभावित होंगे और आए दिन अराजकता के शिकार ईरान में गृहयुद्ध की स्थिति देखने को मिल सकती है।

वुछ रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान की मदद रूस और चीन करेंगे ताकि यह युद्ध काफी दिन चल सके। किन्तु लगता नहीं कि रूस और चीन इस युद्ध में वूदेंगे। रूस तो बिल्वुल सोच ही नहीं सकता क्योंकि ईरान की मदद करके न तो वह अपने देश के यहूदियों को नाराज करेगा और न ही सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे मित्र देशों को।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित स्टडी इन इंडिया एजुकेशन-डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026 में 50 से अधिक देशों के राजनयिकों को संबोधित किया

शिक्षा मंत्री ने विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों से भारत की तेजी से विकसित हो रही नवाचार-संचालित शिक्षा प्रणाली के साथ सहयोग करने का आह्वान किया

सम्मेलन ने वैश्विक शैक्षणिक साझेदारी और राजनयिक मिशनों के साथ जुड़ाव को मजबूत किया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हुई है

भारत विश्व को अध्ययन करने, नवाचार और साथ मिलकर विकास करने के लिए आमंत्रित करता है

(जीएनएस)।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्टडी इन इंडिया एजुकेशन-डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित किया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अधिकारियों ने उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत भारत की शिक्षा प्रणाली में हुए बदलाव का उल्लेख किया और कहा कि भारत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में हो रही महत्वपूर्ण प्रगति और गुणवत्ता, नवाचार तथा सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगी। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सीखने, अनुसंधान, नवाचार और उसे लागू करने के अपार अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका जीवंत ज्ञान तंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री प्रधान ने कहा कि भारत नई शिक्षा नीति 2020 और 'स्टडी इन इंडिया' पहल के माध्यम से छात्रों, शोधकताओं और संस्थानों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर से

लेकर सतत ऊर्जा तक, भारत एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार के रूप में उभर रहा है और सहयोग, क्षमता निर्माण तथा साझा ज्ञान पर आधारित वैश्विक दक्षिण मॉडल को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनिश्चितता और तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा ही समाजों के बीच सबसे मजबूत सेतु है और भारत सहयोगी देशों के साथ ज्ञान के मजबूत सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने राजनयिकों से भारत की तेजी से विकसित हो रही, नवाचार-प्रेरित, बहुविषयक और सुलभ शिक्षा प्रणाली के साथ सहयोग करने का आह्वान किया।

उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले छह वर्षों में भारत के उच्च शिक्षा सुधारों, विशेष रूप से बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास को शिक्षा के साथ एकीकृत करने और अंतर्राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के संदर्भ में स्पष्ट दिशा प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय संस्थान संयुक्त, द्विभाषी और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक जुड़ाव को गहरा कर रहे हैं, जबकि प्रमुख विश्वविद्यालय अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पारदर्शी और समयबद्ध नियामक ढांचा तैयार किया है, जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने में सुविधा हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के प्रमुख संस्थानों के आवेदनों को एक महीने के भीतर मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 'स्टडी इन इंडिया' पहल भारत के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी वैश्विक शिक्षा साझेदारी का खुला निमंत्रण है।

इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए:

भारतीय ज्ञान प्रणाली एक वैश्विक शैक्षणिक पेशकश के रूप में

एसपीएआरसी और जीआईएएन के माध्यम से अकादमिक साझेदारी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत प्रौद्योगिकियां

भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के लिए यूजीसी विनियम 2023

अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर और सहायक ढांचे

भारत की कौशल संरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण

भारत इनोवेट्स 2026

सम्मेलन के दौरान भारत के विकसित हो रहे उच्च शिक्षा तंत्र पर प्रकाश डाला गया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग छात्र गतिशीलता, संयुक्त कार्यक्रम, अनुसंधान साझेदारी और परिसरों की स्थापना शामिल हैं।

स्टडी इन इंडिया एजुकेशन-डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में राजनयिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए भागीदार देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा और अल्पकालिक कार्यक्रमों में भाग लेने, संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित करने और विश्व स्तरीय दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया।

एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 किलोवाट केडब्ल्यू वाइड बैंड गैप (डब्ल्यूबीसी)- आधारित एकीकृत संचालन प्रणाली की शुरूआत की

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए देश में बना 30 केडब्ल्यू वाइड बैंड गैप (डब्ल्यूबीजी) पर आधारित एकीकृत संचालन प्रणाली (आईडीएस) का आज चेन्नई में शुभारंभ किया गया। इस टेक्नोलॉजी को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), तिरुवनंतपुरम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और लुकास टीवीएस के साथ मिलकर नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (एनएएमपीईटी) के तहत तैयार किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सेक्रेटरी श्री एस. कृष्णन ने आईआईटी मद्रास में इसका शुभारंभ किया।

यह लॉन्च एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के एमईआईटीवाई के मिशन में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 30-केडब्ल्यू पावर क्लास भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक यात्री वाहन खंड के लिए खास तौर पर काम की है, जिसमें कॉम्पैक्ट कारें और फ्लीट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अभी, हाई-परफॉर्मेंस ईवी पावरट्रेन सिस्टम और जरूरी सेमीकंडक्टर-बेस्ड ड्राइव

कंपोनेंट का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। ऐसे एकीकृत प्रणाली के स्वदेश में विकसित होने से आयात पर निर्भरता कम होगी, स्थानीयकरण के जरिए सिस्टम की लागत कम होगी, और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ स्केलेबल निर्माण में सहयोग मिलेगा।

इस टेक्नोलॉजी को लुकास टीवीएस के साथ मिलकर सफलतापूर्वक डिजाइन, फैब्रिकेट और वैलिडेट किया गया है और अब यह व्यावसायीकरण और बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए तैयार है। इस एकीकृत संचालन टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक अपनाने से भारत की ईवी आपूर्ति श्रृंखला काफी मजबूत हो सकती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल सिस्टम और कंट्रोल हार्डवेयर में एमएसएमई के लिए मौके बन सकते हैं, और सेमीकंडक्टर-आधारित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। एनएएमपीईटी के जरिए, एमईआईटीवाई अगली पीढ़ी की मोबिलिटी और ऊर्जा प्रणाली के लिए दुनिया भर में प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी बनाने के लिए नवोन्मेषन से चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री एस. कृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' की कल्पना अत्याधुनिक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास से पूरा हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरऔरडी संस्थानों, शैक्षणिक समुदाय और उद्योग के बीच मिलकर किए गए नवोन्मेष से भारत के टेक्नोलॉजी आयात करने वाले देश से टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले और निर्यात करने वाले देश में बदलाव को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 केडब्ल्यू एकीकृत संचालन प्रणाली का विकास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के सफर में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी बताया कि नई शुरू की गई 30 केडब्ल्यू एकीकृत संचालन प्रणाली इलेक्ट्रिक मोटर और इन्वर्टर को एक सिंगल कॉम्पैक्ट, हाई पावर-डेंसिटी यूनिट से जोड़ती है, जो पारंपरिक अलग मोटर-ड्राइव कॉनफि गरेशन की जगह लेती है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह के डिजाइन-आधारित नवोन्मेष से मजबूत घरेलू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को तेज करने और ईवी क्षेत्र में हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इस मौके पर सी-डैक के महानिदेशक श्री ई. मगेश; एमईआईटीवाई के ग्रुप कोऑर्डिनेटर (आईटी और सीसी और बीटी में आरऔरडी) श्री मनोज कुमार जैन; लुकास टीवीएस चेन्नई के सीटीओ श्री रामनाथन एन एस; सी-डैक, तिरुवनंतपुरम के सीनियर डायरेक्टर श्री रेनजी वी चाको; एमईआईटीवाई के वैज्ञानिक ह्यई' डॉ. ओम कृष्ण सिंह; आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर कमलेश हतुआ और उद्योग के प्रतिनिधि मौजूद थे।

वाणिज्य विभाग ने उभरते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की

(जीएनएस)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और निर्यात इकोसिस्टम सहित भारत के निर्यात-आयात (ईएक्सआईएम) कार्गो प्रवाह पर इसके संभावित प्रभाव की समीक्षा करने के लिए सभी हितधारक मंत्रालयों, प्रमुख लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा भागीदारों के साथ एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित किया।

वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव श्री सुचिंद्र मिश्रा और विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) श्री लव अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों और शिपिंग लाइनों/फॉरवर्डर्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्तीय सेवा विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात संवर्धन इकोसिस्टम और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हितधारकों ने बदलते परिचालन परिवेश का आकलन प्रस्तुत किया, जिसमें मार्गों और पारगमन समय में बदलाव, जहाजों के शेड्यूलिंग में समायोजन, कंटेनर/उपकरणों की उपलब्धता, माल ढुलाई और बीमा लागत के रुझान और समय के प्रति संवेदनशील निर्यात पर उनके प्रभावों की जानकारी दी गई। चर्चा में कार्गो आवाजाही में पूवार्नुमान बनाए रखने, अनावश्यक विलंब को कम करने और निर्यातकों व आयातकों के लिए निर्बाध दस्तावेजीकरण और भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

विभाग ने आयात-निर्यात (ईएक्सआईएम) लॉजिस्टिक्स की निरंतरता सुनिश्चित करने और भारत के व्यापार प्रवाह में किसी भी व्यवधान को कम करने की भारत सरकार की प्राथमिकता को दोहराया। इस बात पर जोर दिया गया कि यह दृष्टिकोण सुगम और समन्वित बना रहेगा, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बनाए रखने, निर्यातकों - विशेष रूप से एमएसएमई के हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि घरेलू उत्पादन और उपभोग के लिए आवश्यक आयात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक के दौरान हितधारकों के बीच मार्ग और क्षमता विकास, अधिभार और उपकरण उपलब्धता की वास्तविक समय में निगरानी के लिए निकट समन्वय बनाए रखने पर सहमति बनी। शीर्ष खराब होने वाले उत्पाद, औषधी तथा उच्च मूल्य के विनिर्मित निर्यात जैसे समय-संवेदी क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा तंत्र पर चर्चा की गई। बैठक में पत्तनों एवं अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो पर सुविधा सुदृढ़ करने तथा भीड़भाड़ एवं अधिक समय तक माल रुकने से बचाव पर बल दिया गया। सरकार ने व्यापारिक संचालन को सुगम बनाने के लिए अपनी तत्परता दोहराई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: वास्तविक व्यवधान की स्थिति में निर्यात संबंधी अनुमतियों में प्रक्रियात्मक लचीलापन; सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ समन्वय; निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय और बीमा संस्थानों के साथ संवाद; निरंतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय। विभाग ने इस बात को दोहराया है कि वह भारत के व्यापार को कुशलतापूर्वक संचालित करने और किसी भी उभरते मुद्दे का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

युवा संगम (छठा चरण) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2 मार्च, 2026 से शुरू होंगे

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय ने "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी युवा विनिमय कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए देश भर के 22 उच्च शिक्षा संस्थानों के युवाओं को आमंत्रित किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने आज एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल के तहत युवा संगम -चरण छः के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया।

'युवा संगम' भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रमुख युवा विनिमय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत बनाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह पहल युग्मित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सुनियोजित अनुभव यात्राओं के माध्यम से 'विविधता में एकता' की भावना को बढ़ावा देती है।

18-30 वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक युवा, जिनमें उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र,

एनएसएस/एनवाईकेएस स्वयंसेवक और युवा पेशेवर शामिल हैं, आधिकारिक पोर्टल https://ebsb.aicte-india.org और https://ekbharat.gov.in के माध्यम से आवेदन करने के पात्र हैं।

पिछले युवा संगम चरण-पाँच में उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई, जिसमें देश भर से 46,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए। इसके शुभारंभ के बाद से, 6,000 से अधिक युवाओं और समन्वयकों ने युवा संगम के विभिन्न चरणों (2022 में आयोजित पायलट चरण सहित) जिनका आयोजन देश भर के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा किया गया, में गहन भ्रमण में भाग लिया है । यह अनुभवात्मक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है।

युवा संगम के छठे चरण में, देश भर में 22 उच्च शिक्षा संस्थानों को नोडल संस्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है। चयनित प्रतिभागी अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पांच से सात दिनों की शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राएं (यात्रा के दिनों को छोड़कर) करेंगे।

यह कार्यक्रम पांच मुख्य विषय स्तंभों - 5 पी - पर्यटन (पर्यटन), परंपरा (परंपराएं और संस्कृति), प्रगति (विकास और शासन), पारस्परिक संपर्क (लोगों का आपस में जुड़ाव) और प्रौद्योगिकी और नवाचार (प्रौद्योगिकी और नवाचार) के इर्द-गिर्द संरचित है।

इन स्तंभों के माध्यम से, प्रतिभागी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप सांस्कृतिक विरासत, विकास पहलों, तकनीकी प्रगति, स्थानीय समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होते हैं। युवा संगम को सहभागी मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों, राज्य सरकारों और नोडल उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से "संपूर्ण सरकारी" दृष्टिकोण के तहत कार्यान्वित किया जाता है।

आईएनएस सुदर्शिनी स्वेज नहर से महत्वपूर्ण यात्रा के बाद अलेक्जेंड्रिया पहुंचा

(जीएनएस)।

आईएनएस सुदर्शिनी 01 मार्च 2026 को ऐतिहासिक पोर्ट सिटी अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, जो उसके चल रहे ट्रांसओशनिक अभियान, लोकायन-26 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह जहाज पिछले हफ्ते सफागा से निकलने के बाद स्वेज नहर से उत्तर की ओर यात्रा करने के बाद पहुंचा है। तीन मस्तूल वाले बार्क का 193 किलोमीटर लंबी नहर से गुजरना- जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले दुनिया के ऐतिहासिक समुद्री मार्गों में से एक है- इस वैश्विक यात्रा में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं के लिए यह प्रशिक्षण का प्रमुख आकर्षण रहा है।

अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश 'ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप' पहल को और मजबूत करता है, जो भारत और मिस्र के बीच लंबे समय से चली आ रही समुद्री साझेदारी का उत्सव मनाती है। दोनों देश कई सदियों से सांस्कृतिक संबंधों और आर्थिक संबंधों की एक समृद्ध विरासत साझा करते हैं। हाल के वर्षों में, रक्षा और समुद्री सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। सुदर्शिनी की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

जहाज के पहुंचने पर मिस्र की नेवी और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने रिसीव किया। कमांडिंग ऑफिसर ने अलेक्जेंड्रिया नेवल बेस के कमांडर रियर एडमिरल महमूद अब्देलसत्तार से मुलाकात की। जहाज के ठहराव के दौरान, क्रू प्रोफेशनल एक्सचेंज, कम्युनिटी आउटरीच और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य आपसी सद्भावना बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं

के बीच सहयोग बढ़ाना है।

केंद्रीय भंडारण निगम ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया

केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सीडब्ल्यूसी के 70वें स्थापना दिवस पर भारत की खाद्य सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स विकास में इसके योगदान की सराहना की

(जीएनएस)।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के 70वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया और राष्ट्र को 70 वर्षों की सेवा पूरी करने पर उसे बधाई दी। उन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, भंडारण अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स विकास को मजबूत करने में सीडब्ल्यूसी के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। नई दिल्ली में आयोजित 70वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने संगठन को महारत्न उद्यम बनने की दिशा में प्रयासरत रहने और भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 25 लॉजिस्टिक्स उत्पादक देशों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री जोशी ने कहा कि केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स संगठनों में से एक बनकर उभरा है और अब यह केवल भंडारण गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूसी ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपनी भूमिका का काफी विस्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की स्वीकृति से इसे एक कंपनी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊ में किशोर की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ के कृष्णानगर में सोमवार शाम एक सनसनीखेज वारदात से इलाके को हिला दिया। यहां एक करीब 12 वर्षीय मासूम बच्चे उनैज खान के सिर में की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुरानी लड़ाई का बदला लेने के लिए हत्या की गई।

परिजनों के मुताबिक, उनैज ने रोजा रखा हुआ था। शाम को रोजा खोलने के बाद उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर कार में बिठाकर ले गए थे, जिसके बाद उसका गोली लगा शव मिला है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने बेटे से पूछा भी था कि कोई विवाद तो नहीं है, लेकिन कुछ बताया नहीं। बच्चे की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ।

सरोजनीनगर के बेहसा निवासी उनैज खान (12) कृष्णानगर के बरिगवां में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारोपी कार से उसका शव लोकबंधू अस्पताल की इमरजेंसी में डालकर भाग गये।

भाजपा नेता के भतीजे समेत चार के खिलाफ तहरीर

घटना की जानकारी होने पर पहुंचे पिता जमीर खान ने कृष्णानगर थाने में भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे समेत चार के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है।

वहीं, भाजपा नेता के परिजन के मुताबिक, सभी बच्चे जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए थे। इसी दौरान रील बनाते समय गोली लगने से उनैज की मौत हो गई। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा के मुताबिक रिवाल्वर जब्त कर लिया है। मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है।

सरोजनीनगर के अमौसी स्थित बेहसा निवासी जमीर खान बिजली के उपकरण की दुकान चलाते हैं। जमीर के परिवार में दो बेटे उनैज व उमैज पत्नी शमा है।

जमीर ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 3.30 बजे कृणानगर सेक्टर-बी बरिगवां निवासी भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी का भतीजा व अन्य चालक के साथ उनके घर पहुंचे। जहां उनैज को जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए साथ चलने को कहा।

उनैज ने रोजा खोलने की बात कहा। पर, चारों ने उसे जबरदस्ती साथ लेकर कृष्णानगर के बरिगवां पहुंचे। पूर्व एमएलसी के भाई व नवनीत के पिता संजीव त्रिपाठी के घर के पास पहुंचे। वहां कार में उनैज के माथे पर लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी। उसकी मौत कार में ही हो गई थी। चारों कार से लोकबंधू अस्पताल पहुंचे। वहां उनैज को इमरजेंसी में दाखिल किया। इसके बाद चुपचाप वहां भाग गये।

चार घंटे पर पत्नी के मोबाइल पर दी गई सूचना

जमीर के मुताबिक, उनैज की मौत की सूचना उसके घर से निकलने के चार घंटे बाद दी गई। नवनीत के पिता संजीव त्रिपाठी ने जमीर की पत्नी शमां के मोबाइल पर कॉल कर सूचना दी। परिजन लोकबंधू पहुंचे जहां उसका शव पड़ा था।

परिजन के मुताबिक वहां संजीव त्रिपाठी के दर्जनों करीबी पहुंच गये थे। बेटे का शव देखने नहीं दिया।

मस्कट-रियाद और जेद्दा की तीन उड़ानें बहाल, लखनऊ में 90% तक घटा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक

ईरान-इजरायल/अमेरिका संघर्ष के कारण लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात में 90% की भारी गिरावट आई है।

ईरान-इजरायल संघर्ष से लखनऊ एयरपोर्ट पर यातायात 90% घटा।

खाड़ी देशों की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, यात्री संख्या गिरी।

मस्कट, रियाद, जेद्दा की कुछ उड़ानें सोमवार को बहाल हुईं।

लखनऊ। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल वायु यातायात 90 प्रतिशत तक कम हो गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से खाड़ी देशों को जाने वाली उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। इसके चलते आवाजाही की 18 से 20 इंटरनेशनल उड़ानों की संख्या घटकर दो तक पहुंच गई है।

हालांकि, सोमवार को एविएशन सेक्टर ने थोड़ी सी राहत ली। लखनऊ से जेद्दा, रियाद और मस्कट जाने वाली चार उड़ानें सोमवार को रवाना हुईं। हालांकि यह उड़ानें सलाम एयर, फ्लाईनस व फ्लाई दुबई की रहीं। इसमें भारतीय एयरलाइन ने अभी अपनी उड़ानें नहीं शुरू की हैं। सोमवार को ओमान की उड़ान से मात्र 21 और सलाम एयर की उड़ान से 75 यात्री रवाना हो सके।

18 से 20 इंटरनेशनल उड़ानों की होती है आवाजाही

लखनऊ एयरपोर्ट से प्रतिदिन 18 से 20 इंटरनेशनल उड़ानों की आवाजाही होती है। इसमें से बैंकाक की उड़ान प्रतिदिन रवाना होती है। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीब 17 से 18 हजार यात्री सफर करते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों की संख्या 1500 से 1600 के बीच रहती है। शेष घरेलू उड़ानों के यात्री देश के कई शहरों के लिए अपनी यात्रा करते हैं।

लखनऊ एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानों के यात्रियों की संख्या में सालाना 17 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यात्रियों के साथ-साथ लखनऊ से जो कार्गो से सामान भेजा जाता है, उसमें इंटरनेशनल गंतव्य की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तक है। अब खाड़ी देशों की उड़ानें निरस्त होने से लखनऊ से जाने वाले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या घटकर 110 से 120 रह गई है।

खाड़ी देशों को लखनऊ के अलावा बहराइच, गोंडा, सुलतानपुर, बलरामपुर, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों के युवा रोजगार की तलाश में जाते हैं। करीब 10 से 15 प्रतिशत यात्री दुबई घूमने जाते हैं। इसके अलावा 10 से 15 प्रतिशत लोग ही जियारत के लिए जाते हैं।

सोमवार को निरस्त रहीं यह उड़ानें

सोमवार को लगातार तीसरे दिन खाड़ी देशों की ओर जाने वाली उड़ानों के निरस्त होने का संकट बना रहा। हालांकि लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. की एयर आपरेशन रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को निरस्त उड़ानों की संख्या 17 से घटकर 11 हो गई। जबकि सऊदी अरब और ओमान की कुल आठ उड़ानों का संचालन सोमवार के लिए हो सका।

नीति आयोग और जेआईसीए ने महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहयोगात्मक कार्यों के द्वितीय चरण के लिए चर्चा के अभिलेख पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

भारत-जापान विकास सहयोग को मजबूत करने की दिशा में नीति आयोग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आज "सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्यों के कार्यक्रम को बढ़ावा देने की परियोजना - चरण क्क" के लिए चर्चा अभिलेख (आरओडी) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के श्री रोहित कुमार और जेआईसीए भारत के मुख्य प्रतिनिधि ताकेउची ताकुरो की उपस्थिति रहे।

यह सहयोग भारत-जापान की मजबूत विकास साझेदारी की पुष्टि करता है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों (एडी) और आकांक्षी ब्लॉकों (एबी) में संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाता है। श्री रोहित कुमार ने कहा कि इस साझेदारी में संस्थागत शक्तियां, साझा ज्ञान और जमीनी अनुभव एक साथ है और इसका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति देना है।

एडीपी और एबीपी के अंतर्गत इस परियोजना का उद्देश्य वैश्विक भागीदारी, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा - इन छह विषयों में नीतिगत ढांचों और कार्यान्वयन प्रणालियों को सुदृढ़ करना है। यह परियोजना संस्थागत क्षमता निर्माण, बेहतर निगरानी एवं मूल्यांकन तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी स्थानीयकरण पर केंद्रित है।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में लोगों के बीच आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण सम्बंधी कार्य, जापान-भारत ज्ञान मंच, सर्वोत्तम तौर-तरीकों की पहचान और प्रसार तथा आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों को लक्षित सहायता प्रदान करना शामिल है।

जेआईसीए इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि श्री ताकेउची ताकुरो ने एडीपी और एबीपी के सफल कार्यान्वयन की सराहना करते हुए कहा कि भारत की जिला और ब्लॉक-स्तरीय निगरानी प्रणालियां वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जापान-भारत साझेदारी को और मजबूत करने वाली यह परियोजना पारस्परिक रूप से लाभकारी और सहयोगात्मक पहल है।

नीति आयोग ने राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

(जीएनएस)।

नीति आयोग ने अपने राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) के तहत प्राकृतिक खेती पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें देश भर से किसानों, नीति निमार्ताओं, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप और नागरिकों ने एक साथ भाग लिया।

इस कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक खेती पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षण नियमावली की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य किसानों, विस्तार अधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकताओं को प्राकृतिक खेती पद्धतियों पर क्षेत्र-प्रासंगिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है।

गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने इस कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने टिकाऊ, किसान-केंद्रित कृषि प्रणालियों के महत्व और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, इनपुट लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में प्राकृतिक खेती की भूमिका पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय और गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय सहित प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रही।

पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा के किसानों, कृषि अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती पर विचार-विमर्श किया।

एपीडा, नाबार्ड, सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन विभाग (डीएएचडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख केंद्रीय संस्थानों और मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया और अभिसरण, प्रमाणीकरण, बाजार संबंधों और संस्थागत समर्थन पर अपने विचार साझा किए।

इस कार्यशाला में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप, नागरिकों, अग्रणी किसानों और किसान उत्पादक समूहों ने देश में प्राकृतिक खेती को समर्थन देने वाले बढ़ते इको-सिस्टम पर बल दिया।

कार्यशाला में पहले दिन आयोजित खुली चर्चा में कुल 770 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें किसानों और विशेषज्ञों को प्राकृतिक खेती को अपनाने, प्रमाणीकरण, बाजार और संस्थागत समर्थन से संबंधित अपनी समस्याओं, जमीनी स्तर की चुनौतियों और आशंकाओं पर खुलकर चर्चा करने का अवसर मिला। इस चर्चा में किसान नेतृत्व मॉडलों की आवश्यकता पर आम सहमति बनी।

कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों को जमीनी स्तर पर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का अवलोकन करने और विशेषज्ञों से बातचीत करने का अवसर मिला। इस दौरान विभिन्न विदेशी फसलों के लिए प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के साथ-साथ खेत में और स्वचालन प्रणाली के माध्यम से जैव-उपकरणों की तैयारी को दर्शाया गया।

भारतीय वैज्ञानिकों ने 50 साल पुराने जैविक नियम के पुनर्लेखन में सहायता की

(जीएनएस)।

एक नए अध्ययन की सहायता से जीवाणु जीन विनियमन के प्रमुख पाठ्यपुस्तक मॉडल से अलग हटकर जीवाणु जीन विनियमन और इसके विकास को समझने के लिए नए रास्ते उजागर किए हैं।

इससे संक्रमण तंत्र को अवरुद्ध करने वाले बेहतर एंटीबायोटिक्स या नियामक अवरोधकों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिल सकती है। जो कुशलतापूर्वक जैव ईंधन, जैव अपघटनीय प्लास्टिक या चिकित्सीय यौगिकों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीवों को तैयार करने में मददगार हो सकता है।

लगभग 50 वर्षों से, जीवविज्ञान यह बताता आ रहा है कि जीवाणु तथाकथित "σ (सिग्मा) चक्र" की सहायता से अपने जीन को कैसे सक्रिय करते हैं - ये ऐसे कारक हैं जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर प्रतिलेखन की शुरूआत करते हैं और फिर अलग होकर जीन के विस्तार की अनुमति देते हैं। यह अवधारणा मुख्य रूप से जीवाणु उपभेद ई. कोलाई σ70 के अवलोकनों पर आधारित है।

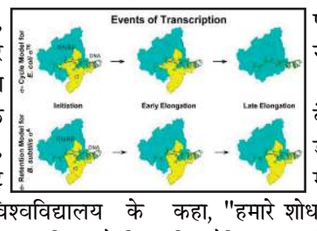

हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, बोस इंस्टीट्यूट और रटगर्स विश्वविद्यालय के शोधकताओं ने खुलासा किया है कि यह चक्र एक सार्वभौमिक घटना नहीं है।

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएएस) की कार्यवाही में प्रकाशित एक अध्ययन में उन्होंने बताया है कि दशकों से चली आ रही वैज्ञानिक मान्यता के विपरीत, बैसिलस सबटिलिस में प्रमुख प्रतिलेखन आरंभिक कारक - σअ - और एस्चेरिचिया कोलाई σ70 कारक का एक संशोधित संस्करण, आरंभिक प्रक्रिया के बाद मुक्त होने के बजाय, प्रतिलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज से बंधे रहते हैं।

बोस इंस्टीट्यूट के प्रमुख लेखक डॉ. जयंता मुखोपाध्याय ने कहा, "हमारे शोध से पता चलता है कि बैसिलस सबटिलिस में , σअ कारक ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा रहता है। इससे बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और जीन विनियमन के बारे में हमारी सोच में मौलिक परिवर्तन आता है।"

जैव रासायनिक परीक्षण, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रिसिपिटेशन और फ्लोरेसेंस-आधारित इमेजिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हुए, शोधकताओं ने सिग्मा कारक के व्यवहार का वास्तविक समय में अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि बैसिलस सबटिलिस σअ और ई. कोलाई σ70 का एक प्रकार जिसमें 1.1 नामक भाग की कमी है, प्रतिलेखन परिसरों के साथ स्थिर रूप से जुड़े रहते हैं। यह पूर्ण-लंबाई वाले ई. कोलाई σ70 के बिल्कुल विपरीत है, जो विस्तार के दौरान अनियमित रूप से मुक्त हो जाता है।

बोस इंस्टीट्यूट के सह-लेखक अनिरुद्ध तिवारी ने कहा, "ये निष्कर्ष इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं कि लंबे समय से स्वीकृत σ चक्र सभी बैक्टीरिया पर लागू नहीं होता है। इससे बैक्टीरिया के जीन नियमन और उसके विकास को समझने के नए रास्ते खुलते हैं।"

21वीं केंद्रीय निगरानी समिति ने प्रदूषित नदी क्षेत्रों और सीवेज प्रबंधन पर राज्यवार प्रगति की समीक्षा की

डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के सचिव ने समयबद्ध कार्रवाई अपनाने और एसटीपी के प्रदर्शन और निगरानी को मजबूत करने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

नदी पुनर्जीवन संबंधी केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) की 21वीं बैठक आज जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग के सचिव श्री वीएल कंथा राव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव कुमार मित्तल सहित वरिष्ठ अधिकारियों, एनएमसीजी के अन्य अधिकारियों और राज्य सरकारों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

समिति ने सीपीसीबी की 2025 की रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषित नदी क्षेत्रों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की और स्वीकृत कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया। अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि नदी के जल की गुणवत्ता में सतत सुधार न केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल्कि उसके प्रभावी उपयोग, नियामक अनुपालन और समय पर परियोजना निष्पादन पर भी निर्भर करता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सीवेज उपचार की कमियों को दूर करना, मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के प्रदर्शन में सुधार करना, चल रही और निविदाकृत एसटीपी परियोजनाओं और सीवेज नेटवर्क के विकास से संबंधित कार्यों में तेजी लाना, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करना, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाना और बाढ़ के मैदानों के सीमांकन में तेजी लाना शामिल थे। सचिव ने राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करने का भी निर्देश दिया।

2018, 2022 और 2025 में पहचाने गए प्रदूषित नदी क्षेत्रों की तुलनात्मक समीक्षा से पता चला कि 2018 से प्रदूषित क्षेत्रों की कुल संख्या में लगातार कमी आई है। हालांकि, जिसके लिए लक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

समिति ने पाया कि कुछ राज्यों ने नए प्रदूषित क्षेत्रों के जुड़ने और विशिष्ट नदी खंडों में गिरावट की सूचना दी है,

समिति ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब के संबंध में सीवेज उपचार संयंत्रों, क्षमता उपयोग, बाढ़क्षेत्र जोनिंग, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और नदी पुनर्जीवन समितियों के माध्यम से संस्थागत निगरानी पर हुई प्रगति की समीक्षा की।

बैठक का समापन राज्यों से नदी पुनर्जीवन के लिए समयबद्ध, परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के आह्वान के साथ हुआ, जिसमें परिचालन दक्षता, अंतर-विभागीय समन्वय और दीर्घकालिक जल गुणवत्ता सुधार प्राप्त करने के लिए निरंतर अनुपालन पर जोर दिया गया।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026: ऐतिहासिक वैश्विक घोषणापत्र और एआई में निवेश के लिए प्रमुख प्रतिबद्धताएं

(जीएनएस)।

16 से 21 फरवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस शिखर सम्मेलन में व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें लगभग 6 लाख प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया जबकि लाइव वर्चुअल स्ट्रीमिंग के माध्यम से 9 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा। 100 से अधिक देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने इस आयोजन में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में "24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने" का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब सफलतापूर्वक हासिल कर किया जिसमें 2.5 लाख से अधिक 'एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञाएं' प्राप्त हुईं। शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा भारत की संप्रभु कंप्यूटिंग क्षमता के विस्तार से संबंधित थी। इंडियाएआई मिशन के तहत पहले से ही उपलब्ध कराए गए 38,000 से अधिक जीपीयू के अलावा, आने वाले हफ्तों में 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़े जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय एआई बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

वैश्विक घोषणाएं और रणनीतिक एआई साझेदारियां

इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार, सुदृढ़ और समावेशी एआई अपनाने के लिए रूपरेखाओं को आगे बढ़ाना था।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया। यह घोषणापत्र शिखर सम्मेलन के दौरान सात विषयगत कार्य समूहों द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देता है।

नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा 13 प्रमुख वैश्विक और भारतीय फ्रंटियर मॉडल डेवलपर्स द्वारा विश्वसनीय और समावेशी एआई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

स्वैच्छिक पहल के अंतर्गत ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स का शुभारंभ हुआ जिसमें 30 से अधिक देशों की 80 से अधिक प्रभावकारी कहानियां शामिल हैं, जो देशों को आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए सफल एआई उपयोग के मामलों को साझा करने, दोहराने और विस्तारित करने में सक्षम बनाती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से इक्विटेबल एआई ट्रांजिशन प्लेबुक का विमोचन किया गया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को एआई-संचालित उभरते अवसरों के लिए तैयार करना है।

लचीली, नवोन्मेषी और कुशल एआई के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें 20 से अधिक देशों ने समर्थन दिया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए।

22 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर को अपनाया गया।

यूनेस्को और फ्रांस के साथ साझेदारी में रेजिलिएंट एआई चैलेंज का शुभारंभ।

सुदृढ़ एआई अवसंरचना को आगे बढ़ाने के लिए प्लेबुक का विमोचन।

औपचारिक शुभारंभ से पहले 22 भागीदार देशों के साथ ट्रस्टेड एआई कॉमन्स की घोषणा की गई।

22 देशों द्वारा अनुमोदित एआई गवर्नेंस पर मार्गदर्शन नोट्स जारी किए गए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशन को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की घोषणा, जिसे 20 देशों और यूनिसेफ का समर्थन प्राप्त है।

विज्ञान संस्थानों के लिए एआई नेटवर्क का शुभारंभ, जिसमें शुरूआत में 19 भागीदार देश शामिल हैं।

एआई इम्पैक्ट एक्सपो, नॉलेज आउटपुट और जमीनी स्तर पर स्वीकार्यता

एआई इम्पैक्ट एक्सपो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी एआई प्रदर्शनियों में से एक के रूप में उभरी, जिसमें 10 विषयगत मंडपों में 850 से अधिक प्रदर्शक शामिल थे।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, एक ओपन-सोर्स हैंडहेल्ड सहायक उपकरण का लाइव प्रदर्शन किया गया, जो आवाज के आधार पर वस्तुओं और परिवेशों को पहचानने और कई भाषाओं में जवाब देने में सक्षम है। भाषिनी और करंट एआई द्वारा विकसित इस प्रोटोटाइप को आगे तकनीकी सुधार और उपयोग के मामलों के विकास के लिए स्टार्टअप जगत के लिए खोल दिया गया।

उच्च प्रभाव वाले एआई परिनियोजनों का दस्तावेजीकरण करने वाली छह वैश्विक केसबुक जारी की गईं जो इस प्रकार से हैं:

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "GARVI GUJARAT" HINDI DAILY AS REQUIRED TO BE PUBLISHED UNDER RULE 8 OF REGISTRATION OF NEWS PAPER. (CENTRAL RULES 1856)

FORM - IV

(SEE RULE - 8)

1.	Place of Publication	**538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh.**
2.	Periodicity of its publication	Hindi Daily
3.	Printer's name	**(1) SUSHILA SHUKLA**
	Whether Citizen of India ?	Yes
	Address	**(1) Krishna Printiers,271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.**
4.	Publisher's name	**AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI**
		131,Dharmanagar Society, Highway Road, **Sabarmati, Ahmedabad- 380 005,Gujarat, India.**
5.	Editor's name	**ASHWANI KUMAR**
	Whether Citizen of India ?	Yes
	Address	**538 GHA/85** Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, **Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh.**
6.	Owners Names And Address	**AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI** **131,**Dharmanagar Society, Highway Road, **Sabarmati, Ahmedabad- 380 005,Gujarat, India.**

I **AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI** here by declare that particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 01-03-2026

Ajaykumar Ramanlal Prajapati
Singaturs of Publisher.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत-डेलावेयर बायो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण कार्य समूह का प्रस्ताव रखा

भारत ने डेलावेयर तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप और अनुसंधान एवं विकास संबंधी लिंकेज की पेशकश की

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत-अमेरिका जैव प्रौद्योगिकी वार्ता में आपूर्ति श्रृंखला और नियामक सहयोग पर जोर दिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को उन्नत जैव-विनिर्माण में एक संरचित भारत-डेलावेयर साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अनुसंधान, विनिर्माण और स्टार्टअप इकोसिस्टम में ठोस सहयोग को लेकर चचाओं को परिणाम में बदलने के लिए एक छोटे कार्य समूह के गठन का प्रस्ताव रखा।

यह प्रस्ताव डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयर के नेतृत्व में आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान सामने आया, जिन्होंने आज यहां सेवा तीर्थ में डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने फार्मा, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार आधारित औद्योगिक विकास में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि भारत उन अमेरिकी देशों के साथ "गहरे जुड़ाव की अच्छी संभावना" देखता है जिनके पास मजबूत नवाचार इकोसिस्टम है। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल के क्षेत्र में नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने पर प्रकाश डाला, जिसकी क्षमता अनुसंधान और विकास से लेकर बड़े पैमाने पर, किफायती विनिर्माण तक फैली हुई है।

सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और स्टार्टअप को जोड़ने वाली भारत की एकीकृत नवाचार संरचना की ओर इशारा करते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि 37 प्रयोगशालाओं और 7,500 से अधिक वैज्ञानिकों वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) देश के अधिकांश औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का आधार है।

लखनऊ में रफ्तार का कहर; कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत

कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में दंपती की जान चली गई. बाराबंकी में भर्ती एक रिश्तेदार का हालचाल जानकर बाइक से लौट रहे दंपती को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. अनौरा कला के पास हुए इस हादसे में देवेंद्र कुमार और उनकी पत्नी सीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया.

टक्कर के कारण काफी दूर गिरे पति-पत्नीः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दंपती बाइक समेत सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे. मूल रूप से बाराबंकी के निवासी देवेंद्र कुमार (38) लखनऊ की एक फैक्ट्री में काम करते थे. वह अपनी पत्नी सीता देवी (36) के साथ चिनहट के बेहटा इलाके में किराए पर रहते थे. सोमवार दोपहर जब वे अपनी बाइक (वढ41 इऊ 3990) से वापस लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित कार ने उन्हें पीछे से रौंद दिया.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौतः दुर्घटना की सूचना मिलते ही बीबीडी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने राहगीरों की मदद से लहूलुहान दंपती को तुरंत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया. घाव इतने गहरे और चोटें इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉक्टरों ने अंततः दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मासूम बच्चों के सिर से उठा सायाः इस हादसे ने दो मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया है. देवेंद्र कुमार के भाई संजीव कुमार ने बताया कि पीछे दो छोटे बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी अदिति रह गए हैं. इन बच्चों की परवरिश और भविष्य को लेकर अब परिवार चिंता में है. पुलिस ने दुर्घटना करने वाली कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

उर्वरक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने श्री रजत कुमार मिश्र (सचिव) की अध्यक्षता में पीएम मोदी के सेवा संकल्प को दोहराया

देशवासियों के प्रति सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण उद्देश्य

(जीएनएस)।

आज उर्वरक विभाग, कर्तव्य भवन में रजत कुमार मिश्र, सचिव, उर्वरक विभाग की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सेवा संकल्प को दोहराया गया तथा इसके उद्देश्य और क्रियान्वयन के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई।

यह आयोजन 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक के अनुरूप था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर्तव्य, सेवा और समर्पण की त्रिवेणी से यह कार्यस्थल एक तीर्थ की भांति पवित्र बने — यही इसकी मूल भावना है।

सेवा तीर्थ में हुई प्रथम बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह संकल्प लिया था कि यहां से लिया गया प्रत्येक निर्णय 140 करोड़ देशवासियों की सेवा भावना से प्रेरित होगा और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा।

आज इसी भावना के अनुरूप श्री रजत कुमार मिश्र (सचिव) के नेतृत्व में उर्वरक विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प को पुनः दोहराया। संकल्प दोहराने के बाद सचिव महोदय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया और सरकार की विभिन्न सकारात्मक उपलब्धियों पर सार्थक चर्चा की. उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इन बदलावों के प्रभाव पर अपने विचार साझा करने को कहा।

इस अवसर पर श्रीमती अपर्णा एस. शर्मा, अपर सचिव ने हर घर शौचालय को एक बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली।

डॉ. कृष्णकांत पाठक, संयुक्त सचिव ने बैंकों का आधार से जुड़ना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जिससे सब्सिडी और सरकारी सुविधाएँ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच सकीं।

इसके अतिरिक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जन-धन योजना, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवाएँ, आधारभूत संरचना का विकास, महिला विकास, आंगनवाड़ी सेवाएँ, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विस्तार, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया।

लखनऊ में आमजन भी देख सकेंगे ब्लड मून, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में की गई व्यवस्था

पूर्ण चंद्रग्रहण तीन को, लखनऊ में दिखेगा आंशिक चरण

लखनऊ में सूर्यास्त 18:08 बजे होगा चंद्रमा उसी समय पूर्व दिशा में क्षितिज के पास होगा उदित

लखनऊ। आमजन भी मंगलवार को चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून का रात में कर सकेंगे। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में इसकी व्यवस्था की गई है। चंद्रग्रहण का लखनऊ में आंशिक दर्शन होगा।

लखनऊ में सूर्यास्त 18:08 बजे होगा और उसी समय चंद्रमा पूर्व दिशा में क्षितिज के पास उदित होगा। उस समय तक पूर्ण चंद्रग्रहण समाप्त हो चुका होगा, लेकिन आंशिक चरण जारी रहेगा। इस दौरान चंद्रमा हल्की लालिमा या धुंधलापन लिए दिखाई दे सकता है।

पूर्ण अवस्था में चंद्रमा के लाल दिखने की घटना को आम भाषा में ह्यब्लड मून' कहा जाता है। वर्ष 2026 का पहला पूर्ण चंद्रग्रहण तीन मार्च की शाम आकाश में दिखाई देगा। यह ग्रहण पूर्ण रूप से लखनऊ में नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका आंशिक चरण देखा जा सकेगा।

मौसम साफ रहने पर शहरवासियों को करीब 39 मिनट तक इस खगोलीय घटना का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम शाम से रात सात बजे तक चलेगा, जिसमें टेलिस्कोप के माध्यम से चंद्रग्रहण का अवलोकन कराया जाएगा। यह कार्यक्रम निःशुल्क रहेगा। आयोजन में उत्तर प्रदेश अमेच्योर एस्ट्रोनामर्स क्लब की भी सहभागिता रहेगी।

विज्ञानी सुमित के अनुसार चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। पूर्णिमा की रात यह घटना संभव होती है। पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी को अधिक बिखेर देता है और लाल रोशनी को आगे बढ़ने देता है, इसी कारण पूर्ण चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देता है।

चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी होने के कारण हर पूर्णिमा पर ग्रहण नहीं लगता। जब तीनों खगोलीय पिंड एक सीध में आ जाते हैं, तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। खगोल प्रेमियों और आम नागरिकों के लिए यह एक अनूठा अवसर होगा, जब वे इस वैज्ञानिक घटना को प्रत्यक्ष देख सकेंगे।

भारतीय रेलवे ने होली पर करोड़ों लोगों को घर पहुंचाया

14 लाख यात्रियों ने पिछले पांच दिनों में उत्तर रेलवे के जरिए यात्रा की; दिल्ली से 1 मार्च को 3.36 लाख लोगों ने प्रस्थान किया

पश्चिम रेलवे ने होली की भीड़ के दौरान 23 लाख यात्रियों को सुविधाएं दीं; उधना से 1 मार्च को 20,000 यात्री रवाना हुए

विशेष ट्रेनें सुनिश्चित करा रहीं आरामदायक, सुरक्षित व समयबद्ध यात्रा

एटीवीएम समर्पित होल्डिंग एरिया और बोतलबंद पानी के वितरण से रेलवे जोनों ने त्योहारी यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाया

सरक्षा से लेकर जमीनी सहायता तकः रेलवे की होली व्यवस्थाओं ने बटोरी जनता की सराहना

(जीएनएस)।

भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे जोनों में सटीक योजना और समन्वित कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि देश भर के यात्री होली के त्योहार के लिए आसानी और आराम से अपने घर जा सकें।

उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर विस्तृत व्यवस्था की

है, विशेष रूप से देश के पूर्वी हिस्सों में होली मनाने के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। आज दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों से 22 विशेष ट्रेनें रवाना हुईं। 01.03.2026 को 22 विशेष ट्रेनें संचालित की गईं और तीन दिन पहले) की तुलना में 18.07% की वृद्धि है।

पिछले पांच दिनों में दिल्ली क्षेत्र से करीब 14 लाख यात्रियों ने सफर किया है। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ की निरंतर निगरानी के आधार पर 03.03.2026 को भी 22 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है। उत्तर रेलवे के अधिकारी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

जोनल रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त फीडबैक व्यवस्थाओं के प्रति यात्रियों की उच्च संतुष्टि को दशार्ता है।

उत्तर रेलवे में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर किए गए विशेष प्रबंध होली से पहले त्योहारों की भीड़ के दौरान यात्रियों की सुचारू और अच्छी तरह से विनियमित आवाजाही को दशार्ते हैं।

आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की सुविधाजनक और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित होल्डिंग एरिया, हेल्प डेस्क बूथ, खान-पान स्टॉल और अतिरिक्त टिकट काउंटर जैसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य तथा खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उपाध्यक्ष सुश्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री ; सह-उपाध्यक्ष सुश्री वंदना गुरनानी, श्रम एवं रोजगार सचिव और सदस्य सचिव तथा श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी उपस्थित थे।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सीबीटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सदस्यों के ईपीएफ खातों में जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खाते में ब्याज जमा करेगा।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ईपीएफओ ने मजबूत वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, जिससे ब्याज खातों पर दबाव डाले बिना स्थिर और प्रतिस्पर्धी रिटर्न सुनिश्चित हुए हैं। यह निर्णय करोड़ों श्रमिकों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करके उन्हें लाभ पहुंचाता है, साथ ही अन्य समान निवेश विकल्पों की तुलना में विवेकपूर्ण, सतत और आकर्षक रिटर्न प्रदान करने और अंशदान की सुरक्षा के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

ईटीएफ और अन्य निवेशों से मिले अच्छे प्रतिफल के कारण ईपीएफओ पिछले कई वर्षों से 8% से अधिक की ब्याज दर घोषित करने में सक्षम रहा है। यह निर्णय ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो की मजबूत साख और अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी प्रतिफल प्रदान करने की इसकी निरंतर क्षमता को दशार्ता है।

इसके अतिरिक्त, डॉ. मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ में सुधारों को जारी रखते हुए निम्नलिखित एजेंडा मदों को चर्चा और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गयाः-

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए माफी योजनाः बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अभी तक शामिल न किए गए या छूट प्राप्त न कर चुके आयकर अधिनियम के अनुपालन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एक बार की माफी योजना को मंजूरी दी है।

जनऔषधि सप्ताह के दूसरे दिन विभिन्न स्थानों पर जनभागीदारी और जागरूकता अभियान में लोगों सशक्त भागीदारी देखने को मिली

(जीएनएस)।

कर्नाटक के उडुपी में स्वास्थ्य जांच शिविर

सप्ताह भर चलने वाले जनऔषधि सप्ताह 2026 के उत्सव ने आज सफलतापूर्वक दूसरे दिन प्रवेश किया। इससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जागरूकता अभियान और भी तेज हो गया है। पहले दिन मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए देश भर में 60 से अधिक स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। यह 7 मार्च 2026 को मनाए जाने वाले 8वें जनऔषधि दिवस की भूमिका के रूप में कार्य कर रहे हैं।

कई स्थानों पर लाभार्थियों को निःशुल्क में सामान्य दवाएं भी मिलीं और कुल मिलाकर प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही। इसमें प्रतिभागियों ने प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्टि व्यक्त की।

बिहार सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती रमा निषाद ने मुजफ्फरपुर जिले के औराई में स्वास्थ्य जांच शिविर का दौरा किया।

झारखंड के जमशेदपुर में स्वास्थ्य जांच शिविर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) 1 से 5 मार्च 2026 तक 250 से अधिक स्थानों पर इस राष्ट्रव्यापी पहल का नेतृत्व कर रहा है।

इन शिविरों में वरिष्ठ नागरिकों और

'जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी - सेहत की बात, बचत के साथ' थीम के साथ ये शिविर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों के घरों तक बुनियादी निदान सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। दूसरे दिन उडुपी (कर्नाटक), जमशेदपुर (झारखंड), देहरादून (उत्तराखंड), जयपुर (राजस्थान), कृष्णा और श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) और झज्जर (हरियाणा) सहित कई स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया।

महाराष्ट्र के नालासोपारा से विधायक श्री राजन नाइक ने पालघर में स्वास्थ्य जांच शिविर का दौरा किया।

महिलाओं की अच्छी खासी संख्या में उपस्थिति रही। स्कूली बच्चों ने भी गतिविधियों में भाग लिया। इससे विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि हुई। सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ, कई स्थानों पर थायरॉइड परीक्षण, बाल चिकित्सा देखभाल और दीर्घकालिक बीमारियों के लिए परामर्श जैसी अन्य नैदानिक सेवाएं भी प्रदान की गईं। इसके अलावा महिलाओं को मासिक धर्म किफायती स्वच्छता उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनऔषधि सैनिटरी पैड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के माध्यम से किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए।

स्वास्थ्य जांच शिविर में हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) के अध्यक्ष श्री राजन्ना कोरिवी

राज्य मंत्री, विधानसभा सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित जन प्रतिनिधियों ने शिविरों का दौरा किया और सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की भूमिका की सराहना की। उन्होंने लोगों को 18,000 से अधिक कार्यरत केंद्रों में से निकटतम केंद्र आसानी से खोजने के लिए 'जन औषधि सुगम' मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

पीएमबीआई ने मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक आवश्यक दवाओं से वंचित न रहे।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 रोडवेज बसों में टक्कर, होली पर घर लौट रहे 3 लोगों की मौत, 31 घायल

उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में हुए सड़क हादसे के बाद रात भर चीत्कार मचा रहा। आगरा डिपो की बस पहले ट्रक से टकराई। इसके बाद मथुरा डिपो की बस ने भी उसको टक्कर मार दी।

(जीएनएस)।

उन्नावः उत्तर प्रदेश के उन्नाव में होली के मौके पर अपने घर लौट रहे बस सवार लोगों के साथ बड़ा हादसा हो गया। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ इलाके में रविवार रात दो रोडवेज बस में टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 31 गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों की मौत के बाद उनके घरों में चीख पुकार मच

गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दरअसल, रविवार देर रात आगरा डिपो की बस लखनऊ की तरफ जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार बस आगे जा ट्रक में जा घुसी। रेस्क्यू टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। हादसे में घायल 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि थाना बांगरमऊ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

उन्नाव पुलिस

मथुरा डिपो बस का अगला हिस्सा चकनाचूर

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रोडवेज बस एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़ी थी। इसी दौरान मथुरा डिपो की एक बस ने सड़क किनारे खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मथुरा डिपो की बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।

17 गंभीर घायल लखनऊ रेफर

मथुरा डिपो में सवार 20 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। इनमें से तीन की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। 17 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया गया है। घायलों में ज्यादातर पूर्वांचल के लोग थे जो होली पर घर वापस जा रहे थे। राहत और बचाव कार्य में टीमें रात भर मुस्तैदी से जुटी रहीं।

निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर युवक से ऐंठी रकम

लखनऊ के कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

लखनऊ। जमीन में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर जालसाज ने 19 लाख रुपये ठग लिए। पांच वर्ष में दो गुना रकम करने का झांसा दिया था। चारबाग निवासी पीड़ित ने डीसीपी दक्षिणी से शिकायत की। जांच के बाद तीन आरोपितों के खिलाफ कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

चारबाग निवासी राकेश कुमार सिंह के मुताबिक, सितंबर 2016 में उनके परिचित राहुल पाठक ने खुद को सेल्स मैनेजर बताया। कहा कि कंपनी में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा होगा।

राहुल ने कंपनी के निदेशक विनय पाठक और रंजना पाठक से मुलाकात कराई। तीनों ने मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड स्थित जमीन दिखाकर निवेश पर पांच वर्ष में लाभांश सहित दो गुना रकम लौटाने और जमीन देने का आश्वासन दिया। राकेश के मुताबिक, 20 नवंबर 2016 से दो फरवरी 2018 के बीच चेक व ऑनलाइन और नकद मिलाकर 19 लाख रुपये निवेश किया। काफी समय बीतने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। न ही कोई लाभ दिया गया। शिकायत करने पर आरोपितों ने 2021 में तीन लाख रुपये के दो चेक दिये। जो भुगतान के लिए लगाते ही बाउंस हो गया।